International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 04, No. 02(II), April - June, 2022, pp. 286-292

विमुद्रीकरणः नकद रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता भारत

दिलीप कंवरिया*

सार

विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें चलन मुद्रा (मुख्यत बड़े नोट) अवैध घोषित कर दी जाती है। जब अर्थव्यवस्था में कालाधन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो सरकार देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान से बचाने के लिए ऐसा कदम उठाती है। इसके साथ – साथ आतंकवाद के लिए आर्थिक मदद, कर चोरी, तस्करी, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के समाधान के लिए विमुद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाती है। बैंकिंग व मुद्रा आपस में जुड़े हुए है। एक रुपए के नोट एवं सिक्कों को छोड़कर हमारे देश में सारे नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक हमारे देश का केन्द्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक मुद्रा के वितरण का कार्य विभिन्न श्रेणियों के बैंकों जैसे सरकारी बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि के माध्यम से करता है। 8 नवम्बर 2016 की रात को भारतीय सरकार द्वारा 500 व 1000 रु. के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया गया और उन्हें चलन से बाहर कर दिया गया। आंकड़ों की मानें तो इन नोटों का मूल्य देश की कुल नकदी में 85 प्रतिशत था, जो कि अमेरिका व जापान के बड़े नोटों के प्रतिशत जितना ही था। विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल बैंकिंग और नकद रहित लेनदेन की मात्रा में वृद्धि हुई व डिजिटल भुगतान में भी वृद्धि हुई। आंकड़ों के मुताबिक इस समय हमारा देश नकद रहित वाले समाज की ओर अग्रसर हो रहा है।

शब्दकोशः *विमुद्रीकरण, कालाधन, अर्थव्यवस्था, डिजिटल बैंकिंग।*

प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा 8 नवम्बर 2016 को अचानक 500 व 1000 रुपयें के नोटों को बन्द कर दिया, जिसके कारण देश में एक तरह की आपातकाल घोषित हो गया। निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक के लोगों को इस निर्णय की वजह से एक – एक रुपये के लिए झूजते हुए देखा गया। एक लम्बे समय तक लोगों को बैंकों एवं विभिन्न ए.टी.एम. के बाहर लम्बी कतारों में खड़ा होना पड़ा। सरकार द्वारा कहा गया कि यह कदम भारत में नकदी रहित अर्थव्यवस्था का विकास करने की दिशा में उठाया गया कदम है। पूरे देश में बड़े पैमाने पर इसका विरोध भी किया गया। विमुद्रीकरण के पश्चात जो कठिनाईयाँ देश भर में महसूस की गई, उनका दौर अब धीरे – धीरे थमने लगा है और लोग डिजिटल माध्यमों द्वारा भुगतान करने को सुरक्षित एवं सुविधाजनक मानने लगे है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.6 प्रतिशत के विकास दर को प्राप्त कर लेगी। साथ ही अर्थव्यवस्था में पर्याप्त नकदी भी आ जाएगी। भविष्य में धीरे – धीरे नकद रहित अर्थव्यवस्था (कैशलेस अर्थव्यवस्था) को पूरी तरह से अपना लिया जाएगा। वर्तमान में भारत में धीरे – धीरे नकदी केंद्रित अर्थव्यवस्था से नकदी रहित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ता जा रहा है।

साहित्य का पुनरावलोकन (Review of Literature)

सुनिता सरकार (2010) ने अपने शोधपत्र में कालेधन को अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होने भारतीय राजनीति में कालेधन की स्थिति का जिक्र किया।

---

* शोधार्थी, (ई.ए.एफ.एम.) वाणिज्य विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय., अजमेर, राजस्थान।

Tax Research Team (2016) ने अपने शोधपत्र में भारमीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले विमुद्रीकरण के प्रभावों की व्याख्या की।

Das agarwal (2010) "Cashless payment System in India a roadmap" में वर्तमान व भविष्य में नकदरहित लेन – देन के महत्व को दर्शाया और साथ – साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकद रहित के प्रभावों की व्याख्या की।

Barker (1992) ने अपने अध्ययन "Globalization of Credit Card usage : The case of a developing economy" में तुर्की की अर्थव्यवस्था में नकदरहित अर्थव्यवस्था में क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता का विश्लेषण किया।

Joshi (1996) ने अपने अध्ययन "Variants of Plastics" में डेबिट व स्मार्ट कार्ड का रोजमर्रा की जिन्दगी में बढ़ते योगदान को बताया।

शोध प्रविधि (Research Methodology)

प्रस्तुत शोध पत्र सम्पूर्ण रुप से द्वितियक आंकड़ों पर निर्भर है। उक्त शोध पत्र में आंकड़ों के संग्रहण हेतु शोध पत्र – पत्रिकाएं, समय – समय पर प्रकाशित की जाने वाली पुस्तके व रिपोर्ट्स, समाचार पत्र व सम्बन्धित वेबसाइटों के माध्यम से एकत्र किया गया है। जिससे शोध के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

शोध के उद्देश्य (Objective of the Study)

प्रस्तुत शोध पत्र के निम्न उद्देश्य हैः

- विमुद्रीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को समझाना।
- नकद रहित अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण के प्रभाव का पता लगाना।
- भारतीय जनता पर विमुद्रीकरण का प्रभाव का पता लगाना।

वर्तमान स्थिति (Present Position)

विमुद्रीकरण के पश्चात पैदा हुई समस्याओं का दौर खत्म हो चुका है। आर्थिक गतिविधियां बहाल हो रही हैं। बैंकों के पास विकास के लिए ऋण देने की काफी रकम आ चुकी है। चूंकि यह पैसा कम लागत वाली जमा रकम है, इसलिए इससे निश्चित तौर पर ब्याज दरें कम होंगी। दोनों चीजें पहले ही हो चुकी हैं। जो लाखों करोड़ो रुपये तरल मुद्रा की तरह बाजार में इधर–उधर थे, वे अब बैंकिंग प्रणाली में आ चुके हैं। इससे न सिर्फ पैसे की गोपनीयता खत्म हुई है, बल्कि इसके मालिक कर देकर इस रकम का ज्यादा प्रभावी उपयोग कर पाएंगे। बैंकिंग लेन–देन और अर्थव्यवस्था का आकार निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। मध्यम और लंबी अवधि में जीडीपी बड़ी और साफ होगी। बैंकिंग प्रणाली में पैसा आने और इसके आधिकारिक लेन–देन से ज्यादा कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों के लिए गुंजाइश बनेगी। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इससे फायदा होगा। साथ ही बड़े पैमाने पर डिजिटल लेन–देन से अर्थव्यवस्था को भी मदद मिलेगी।

- **नकदरहित अर्थव्यवस्था के लाभ :** भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन यह कालाधन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अवैध संपत्ति आदि मुद्दों से पीड़ित है। भ्रष्टाचार और कालेधन के शिकंजे को तोड़ने के लिए लेखा–परीक्षा और प्रवर्तन अभिकरणों जैसे विभिन्न तरीके हमेशा मौजूद रहे हैं, लेकिन नगदरहित अर्थव्यवस्था का विचार अधिक आकर्षक है क्योंकि अधिकतर आर्थिक लेन–देन एक औपचारिक प्रणाली का हिस्सा होंगे तथा उन पर नजर रखना आसान होगा। भारत में बहुत कम लोग ही गैर–नगदी भुगतान के तरीकों का प्रयोग करते हैं। केवल 10–15 प्रतिशत आबादी ने ही कभी–भी किसी प्रकार के गैर–नगदी भुगतान उपकरण का उपयोग किया है, जबकि ब्राजील और चीन जैसे देशों में यह आंकड़ा 40 प्रतिशत तक है। हम नकदी रहित अर्थव्यवस्था के लाभों को निम्न बिन्दुओं द्वारा समझ सकते है।

- **भगुतान का सुविधाजनक तरीका :** लेन–देन में आसानी के कारण यह निश्चित रूप से नगदरहित होने को बढ़ावा देता है। नगदरहित अर्थव्यवस्था सभी को (निम्न–आय वर्ग को छोड़कर) नकदी में व्यापार या लेन – देन करने की लागत में कमी समेत ढ़ेरों लाभ प्रदान करती है।
- **कम जोखिम :** समुचित साइबर–सुरक्षा के साथ ऑनलाइन भगुतान अपेक्षाकृत जोखिम मुक्त है, जबकि भौतिक नगदी के साथ हमशेा सुरक्षा की समस्या रहती है।
- **मुद्रा छापने की लागत में कमी :** नए नोट छापने और गंदे एवं कटे–फटे नोटों को बदलने में काफी लागत आती है। 2015 में आरबीआई को नोट छापने में 27 बिलियन रुपए की लागत आई। अगर हम एक नगदरहित समाज की ओर बढ़ते हैं तो यह लागत कम की जा सकती है।
- **अपराध–दर में कमी :** नशीले पदार्थों की तस्करी, वेश्यावृत्ति, आतंकवाद का वित्तपोषण और कालेधन को वैध बनाने जैसी ज्यादातर समाज–विरोधी एवं अवैध गतिविधियों को केवल नकदी में ही अंजाम दिया जाता है। एक नगदरहित अर्थव्यवस्था में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देना कठिन होगा।
- **बैंकिंग क्षेत्रों के लिए बेहतर :** एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बैंकिंग प्रणाली की मदद करेगी। एक बार लोग डिजिटल भुगतान एवं अंतरण के आदी हो जायेंगे तो नकदी साथ रखने या नकदी की जमाखोरी में कमी आएगी।
- **पारदर्शिता एवं निगरानी :** सरकार नगदरहित लेन–देन की आसानी से निगरानी कर सकती है। अतः कर अपवंचन कठिन होगा और इससे राजस्व–संग्रह में वृद्धि होगी।

नगदरहित समाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

विमुद्रीकरण के कुछ समय बाद ही सरकार ने लोगों को प्रोत्साहित करने तथा विभिन्न डिजिटल तरीकों को अपनाने के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए।

- **उपभोक्ताओं के लिए लकी ग्राहक योजना और व्यापारियों के लिए डिजिधन व्यापार योजना**: डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार ने 25 दिसंबर 2016 को डिजिटल लॉटरी योजनाओं– जैसे उपभोक्ताओं के लिए लकी ग्राहक योजना तथा व्यापारियों के लिए डिजिधन व्यापार योजना की शुरुआत की। इस तरह की प्रोत्साहन योजनाओं के साथ डिजिटल इंडिया आन्दोलन निश्चित रूप से देश के आर्थिक आधार को सुदृढ़ बनाएगा। रूपे कार्ड, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लेमेंट्री सर्विस डाटा, यूएसएसडी, यूपीआई और आधार समर्थित भुगतान प्रणालियां इन योजनाओं का हिस्सा हैं।
- **वित्तीय साक्षरता अभियान :** वित्तीय साक्षरता अभियान की शुरुआत एक डिजिटल अर्थव्यवस्था और लेन–देन के नगदरहित तरीकों को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य डिजिटल तरीकों को अपनाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना, उन्हें प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना है।
- **बीएचआईएम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) :** प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर, 2016 को ऑनलाइन लेन–देन को आसान बनाने के लिए बीएचआईएम नामक ई–वॉलेट एप की शुरुआत की। इस आधार–आधारित मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने बैंक खाते से सीधे भुगतान कर सकता है। केवल आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए और उसके बाद धन अंतरण के लिए बस एक क्लिक की ही देरी है। हालांकि यह एप यूपीआई–समर्थित बैंक खातों के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन एक समय पर केवल एक ही खाता इससे जोड़ा जा सकता है। जिसके पास दो खाते हैं उसे दोनों खातों से लेन–देन के लिए एक खाते से दूसरे खाते पर जाना होगा।
- **रूपे कार्ड क्रेडिट या डेबिट कार्ड** का भारतीय सस्करण है और यह वीसा या मास्टरकार्ड जैसे अतंरराष्ट्रीय कार्ड के समान है। भारतीय राष्ट्रीय भगुतान निगम (एनपीसीआई) ने जन–धन योजना के तहत रुपे कार्ड की शुरुआत की।

- **आधार भगुतान एप :** 25 दिसबंर, 2016 को सरकार ने एक आधार एप की शरुआत की। यह किसी व्यक्ति के बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ता है। यह एप एक बायोमैट्रिक रीडर से जुड़ा होगा और उपभोक्ता अपनी आधार सख्या दर्ज करेगा और अतंरण के लिए एक बैंक का चनुाव करेगा।

नगदरहित अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां

विमुद्रीकरण ने पूरी अर्थव्यवस्था को कम नकदी के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन लोगों और साथ ही सरकार के सामने इसने कुछ चुनौतियां भी पेश की हैं। डिजिटल होने के मुद्दे पर भारत में आम सहमती है। लेकिन क्या समुचित बुनियादी ढांचे के बगैर यह संभव है? ग्रामीण क्षेत्रों में, सार्वजनिक बैंकों तथा स्टेट बैंक समूह के एटीएम केवल 20.8 प्रतिशत हैं और निजी क्षेत्रों के बैंकों के एटीएम 8.5 प्रतिशत हैं। ग्रामीण क्षेत्राों में एटीएम मिलना बहुत मुश्किल है। ई–वॉलेट और मोबाइल भुगतान प्रणाली के लिए एक स्मार्टपफोन और इंटरनेट की जरुरत होती है, लेकिन आबादी के चौथाई से भी कम हिस्से के पास स्मार्टपफोन हैं, तेज और भरोसेमंद इन्टरनेट सेवा महंगी है और मिलनी मुश्किल है। सार्वजनिक वाई–पफाई, हॉटस्पॉट और मोबाइल पफोन बैटरी चार्जिंग स्टेशन भी कुछ गिने–चुने ही हैं और साइबर सुरक्षा भी चिंता का विषय है। किसी को कैसे भरोसा होगा कि छोटी दुकानों और फेरीवालों के पास कार्ड स्वाईप करना सुरक्षित है और उनके कार्ड का विवरण गोपनीय रहेगा? यदि कार्ड का विवरण चुरा लिया गया तो, किसी व्यक्ति के लिए बड़ी मेहनत से कमाई गयी राशि की भरपाई करने में उसको कई साल लग जायेंगे। अक्तूबर 2016 में, 30 लाख से अधिक डेबिट कार्ड के विवरणों के लीक होने का खतरा हो गया था और ग्राहकों से अपने पिन बदलने के लिए कहा गया था। एक महीने बाद जब विमुद्रीकरण के कारण कार्ड से लेन–देन अचानक बढ़ा, तो नेटवर्क पर काफी भार आ गया, कार्ड मशीनों ने काम करना बंद कर दिया और लोगों को लंबी–लंबी कतारों में घंटों लगना पड़ा।

साइबर सुरक्षा

कमनगद अर्थव्यवस्था में साइबर अपराधों का खतरा चिंता का प्रमुख कारण है। लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर काफी सजग है। साइबर हमले से बचने के लिए अनेक उपाय किए गए है, ताकि डिजिटल लेन–देन को सुरक्षित बनाया जा सके। इसके लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षित जानकारी का मकसद सूचना की गोपनीयता, समग्रता और उसकी उपलब्धता है। इन तीनों मानकों को सुरक्षा सेवा या सुरक्षा लक्ष्य कहते हैं। सुरक्षा से जुड़े दूसरे उद्देश्यों में खबर की सच्चाई, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता हैं। यह प्रणाली चित्र 1 में दिखाई गई है। साइबर सुरक्षा, एक प्रकिया और तकनीक या सुरक्षा से जुड़े मकसदों को हासिल करने का एक तरीका है। साइबर सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, सिस्टम्स सुरक्षा, इंटरनेट सुरक्षा के लिए कई टर्म का इस्तेमाल होता है।

चित्र 1: सूचना सुरक्षा लक्ष्य के विभिन्न पक्ष

ऑनलाइन बैंकिंग को एक उदाहरण के जरिए समझा जा सकता है। ग्राहक के खाते का ब्योरा जैसे नाम, पता, बैंक बैलेंस और लेन–देन जैसी जानकारियां किसी भी बैंक के लिए उसके ग्राहकों के लिहाज से काफी अहम हैं। इस तरह की जानकारियों को सुरक्षित रखने की जरूरत होती है। ऐसी सूचनाओं की जानकारी सिर्फ बैंक के अधिकृत अधिकारियों या कर्मचारियों और ग्राहक को ही होनी चाहिए। अगर ये सूचनाएं लीक होती हैं, तो इसे सुरक्षा भंग मानी जाती है। ठीक इसी तरह ग्राहक और बैंक के बीच का संचार भी सुरक्षित रहना चाहिए। ग्राहक जो संदेश बैंक को देते हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए।

चित्र 2: सुरक्षित लॉग इन (ताले का चिह्न हरे रंग मे)

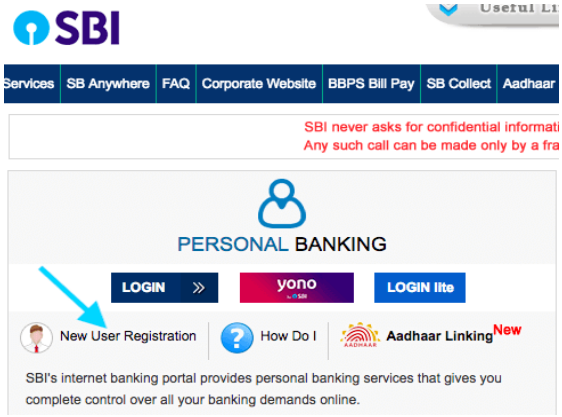

चित्र 2 में सुरक्षित लॉग–इन साइट दिखाई गई है। ध्यान दीजिए इसके यूआरएल में बैंक के नाम के साथ बंद ताले का निशान होगा। यह इस बात का संकेत है कि आप एक सुरक्षित सिस्टम में लॉग–इन कर रहे हैं।

चित्र 3: बहुस्तरीय साइबर सुरक्षा संरचनाएं

साइबर हमलों से बचने के लिए एक प्रणाली बनाई गई है। बड़े – बड़े संस्थानों में साइबर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते है, जो उन्हें होने वाले हमलों के लिए सचेत करते है। सामान्य तौर पर सुरक्षा की परतों को हम चित्र नं. 3 के द्वारा समझ सकते है। आंकडे, अनुप्रयोग, होस्ट, नेटवर्क और इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए एक टीम नियुक्त की जाती है।

चित्र 4: बहुस्तरीय साइबर सुरक्षा संरचनाएं

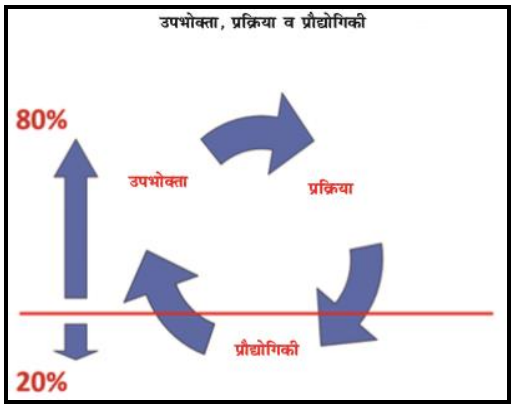

साइबर सुरक्षा का प्रबंधन 'उपभोक्ता, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी' की प्रणाली के जरिए होता है। जैसा कि तस्वीर नंबर 4 में दिखाया गया है। सुरक्षा में प्रौद्योगिकी से ज्यादा उस प्रक्रिया से जुड़े प्रौद्योगिकी का योगदान होता है। प्रौद्योगिकी को जिस तरह लागू किया जाता है वह उसी तरह काम करती है, लेकिन इंसानी बर्ताव अलग–अलग समय पर अलग होता है। यह संस्कृति में बदलाव के साथ व्यक्ति की प्रक्रिया और प्रबंध पर निर्भर करता है।

पासवर्ड सुरक्षित रखने के लिए सुझाव

- यह 8 से 10 शब्दों होना चाहिए, इसमें अल्पफाबेट्स और अंक ही ज्यादा बेहतर है।
- इसमें लोअर केस और अपर केस का समन्वय होना चाहिए।
- पासवर्ड में खास कैरेक्टर जरूर डालें।
- पासवर्ड अलग – अलग भाषा में होना चाहिए, जिसे पता कर पाना मुश्किल हो।
- कुछ दिनों के भीतर पासवर्ड बदलते रहना चाहिए।
- पासवर्ड में नाम, पता, जन्मदिन आदि डालने से बचना चाहिए।

उपाय

सुरक्षा के उपाय : डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स के लिए :

- अपने साधनों को लगातार अपडेट करते रहना चाहिए।
- हमेशा पासवर्ड का प्रयोग करते रहना चाहिए।
- आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड्स करना चाहिए।
- समय – समय अपने सिस्टम को ऑफ करें।
- यूएसबी ड्राइव इस्तेमाल करते हुए हमेशा सावधान रहना चाहिए।
- ऑनलाइन बैंकिंग जैसे काम अपने निजी कंप्यूटर से ही करें।
- हमेशा अपने सिस्टम पर बैकअप लेते रहना चाहिए।
- सोशल नेटवर्कस और मीडिया पर शेयर करने से पहले सोचें।

संस्था, सिस्टम, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए सुरक्षा के उपाय

- प्रबंधन में सुरक्षा पॉलिसी का प्रयोग करना चाहिए।
- सुरक्षा पॉलिसी सभी कर्मचारियों की समझ में आनी चाहिए।
- समय–समय पर अपने उपायों की जांच करें।
- नियमित तौर पर सुरक्षा तरीको का इस्तेमाल करना चाहिए।
- सिस्टम का बैकअप लेते रहना चाहिए और उसे चेक करते रहना चाहिए।
- अलग–अलग कार्यों के लिए पासवर्ड का इस्तेमाल करें ।
- अंत में साइबर सुरक्षा के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराती है। यह ऑनलाइन बैंकिंग और मौजूदा नगदरहित अर्थव्यवस्था के लिहाज से कापफी अहम है। साइबर सुरक्षा भी एक ऐसा क्षेत्रा है जहां युवा इंजीनियर अपना करियर बना सकते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

किसी भी अर्थव्यवस्था में 100 फीसदी नगदरहित समाज के लक्ष्य को प्राप्त करना कभी–भी संभव नहीं हो सकता है, लेकिन हम नकद रहित से कम नकदी वाले समाज की शुरुआत कर सकते है और फिर धीरे – धीरे नगदरहित समाज की ओर अग्रसर हो सकते हैं। नगदरहित समाज की ओर बढ़ना हमेशा से ही लाभप्रद

रहा है। फिर भी नकदी का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। छोटे – छोटे कार्यो के लिए तथा दूर – दराज के क्षेत्रों में होने वाले लेनदेनो में नकदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भविष्य में आने वाली तकनीकों के साथ, ऐसे सॉफटवेयर तैयार करने होगें, जिसमें बहुत अनौपचारिक खरीद का भुगतान भी खरीददार के बैंक खाते से सीधे काट लिया जायेगा। अगर नकदी का व्यवहार अर्थव्यवस्था में कम हो जाता है तो ज्यादातर लेन–देन डिजिटल हो जाएंगे और परिणामस्वरुप लोग अपने साथ कम नकदी रखेंगे। वित्तीय लेन–देन का डिजिटलीकरण भारत में चल रही समानांतर अर्थव्यवस्था को रोकने का प्रभावशाली साधन साबित हो सकता है। इससे रिकॉर्ड रखने में आसानी हो जाएगी और कर–आधार भी बढ़ेगा तथा नकदी साथ रखने की जरुरत कम रहेगी और कर – चोरी की दर भी कम हो जाएगी। जाली मुद्रा और उसका प्रयोग सम्भवतः समाप्ति की ओर अग्रसर होगा और अर्थव्यवस्था में काला धन अपने अन्तिम दौर में पहुँच जाएगा और कालेधन को वैध बनाना कठिन हो जायेगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने *कमनगद अर्थव्यवस्था* की दिशा में आगे बढ़ने में सही कदम उठाया है। हालांकि, बाकि देशों का अनुभव यह दिखाता है कि *कमनगद अर्थव्यवस्था* में अवसंरचना और इसे सहारा देने वाले नियमों की जरूरत होती है। *कमनगद अर्थव्यवस्था* की तरफ बढ़ने के लिए सरकार, वित्तीय संस्थान और कारोबार को मिलकर काम करना होगा। इसके अलावा, देश में कर की दर कम और इसका ढांचा आसान होना चाहिए।

अन्ततः हम यह कह सकते है कि अन्य देशों की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में नकद रहित लेनदेनों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। भविष्य में डिजिटल माध्यमों द्वारा नकदी का इस्तेमाल ओर कम होने वाला है। जिससे एक नए नकद रहित समाज की स्थापना होगी और देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उनसे धीरे – धीरे मुक्ति मिल जाएगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. www.idrbt.ac.in
2. www.rbi.com
3. www.google.com
4. www.wikipedia.com
5. Bank Quest (July - Sep 2017).
6. www.Demonitisation.com
7. www.wikipedia.in
8. www. ebanking in India.com
9. www. scotbuzz.com
10. www. rbi.com
11. www. e-banking in India.com
12. http://www.financialexpress.com
13. http://www.internetworldstats.com
14. economics times, ebanking survey 2009
15. सुनिता सरकार (2010)
16. Tax Research Team (2016)
17. Das agarwal (2010) "Cashless payment System in India a roadmap
18. Barker (1992 "Globalization of Credit Card usage
19. Joshi (1996) "Variants of Plastics"

❖◆❖